

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

1997  
9/12/97

सं० 189 ]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 1997/आश्विन 7, 1919

No. 189 ]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 1997/ASHVINA 7, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1997

**विषय :** पीवीसी रेजिन के आयातों के संबंध में प्रतिपाटन शुल्कों की समीक्षा अंतिम निष्कर्ष

एडीडी/आई डब्ल्यू/53/96-1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (डम्प की गई मदों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिज्ञान आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति-निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए ;

**क. कार्यविधि**

1. नीचे दी गई कार्यविधि अपनाई गई है :
- I. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा) ने 30 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. ए डी डी/आई डब्ल्यू/53/96 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसमें ब्राजील, कोरिया गणराज्य (जिसे बाद में कोरिया अथवा कोरिया आरपी कहा जाएगा), मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमरीका (जिसे बाद में यू.एस.ए. कहा जाएगा) के मूल के या वहां से आयातित पोलि विनायल क्लोराइड रेजिन (जिसे बाद में पीवीसी रेजिन कहा जाएगा) के आयात पर दिनांक 30 जुलाई, 1993 की अधिसूचना सं. 14/4/92-टीपीडी द्वारा सिफारिश किए गए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क तथा केन्द्रीय सरकार की 18 जनवरी, 1994 की अधिसूचना सं. 4/94 द्वारा लगाए गए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा शुरू की गई थी।
- II. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 30 जुलाई, 1993 की अधिसूचना सं. 14/4/92-टीपीडी द्वारा दिए गए जांच निष्कर्षों को पिछली जांच कहा गया है।
- III. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 30 सितम्बर, 1996 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी जिसमें सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के सीमाशुल्क शीर्ष 3904 के तहत वर्गीकृत ब्राजील, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको तथा यू.एस.ए. (जिन्हें बाद में संबद्ध देश कहा जाएगा) मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी रेजिन के आयात के संबंध में प्रतिपाटन शुल्कों की समीक्षा शुरू की गई थी।
- IV. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों तथा उद्योग के प्रतिष्ठानों को (जिनके संबंध में ब्यौरे पूर्व की जांच में पीवीसी रेजिन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए थे) सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी थी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें लिखित में अपने विचारों को भेजने के लिए अवसर प्रदान किया गया था।

(1)

- V. प्राधिकारी ने भारत में पी वी सी रेजिन के उपभोक्ताओं की सभी ज्ञात संस्थाओं को (जिनका ब्यौरा पिछली जांच में प्रेमा द्वारा दिया गया था) सार्वजनिक सूचना की प्रति उपलब्ध कराई गई थी तथा उन्हें सलाह दी गई थी कि वे इस पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं।
- VI. समीक्षा की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में किए गए पीवीसी रेजिन के आयात के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड से अनुरोध किया गया था। बहरहाल, सीबीईसी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।
- VII. नियम 6 (4) के अनुसार प्राधिकारी ने निम्नलिखित निर्यातकों से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रश्नावली भेजी थी :
- \* बिस्टा कैमिकल कंपनी, यू.एस.ए.
  - \* शिनटैक इंक, यू.एस.ए.
  - \* बोर्डन कैमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, यू.एस.ए.
  - \* फोरमसा प्लास्टिक्स कारपोरेशन, यू.एस.ए.
  - \* लक्की गोल्डस्टार इंटरनेशनल, कोरिया गणराज्य
  - \* होंगयांग कैमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
  - \* ग्रुपो प्राईमैक्स एस.ए. डीई सी.वी. मैक्सिको
  - \* यू.बी. इंटरनेशनल, सिंगापुर
  - \* विनमार इंक, यू.एस.ए.
  - \* कम्पैनहिया पेट्रोक्वीमिका, ब्राजील
  - \* कुंस्टोप्लास्ट आफ अमरीका इंक, यू.एस.ए.
- लेकिन, किसी भी निर्यातक ने इस प्रश्नावली का उत्तर नहीं भेजा।
- VIII. संबंध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को नियम 6 (2) के अनुसार समीक्षा की शुरुआत करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचना भेजी गई कि वे अपने अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर भेजने की सलाह दें। निर्यातकों को भेजे गए पत्र तथा प्रश्नावली की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ दूतावासों में भी भेजी गई।
- IX. भारत में पी वी सी रेजिन के उपभोक्ताओं के निम्नलिखित संघों को प्रश्नावली भेजी गई जिसमें नियम 6 (4) के अनुसार सूचना मांगी गई थी :—
- \* आर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक्स प्रोसेसर्स आफ इंडिया, मुंबई
  - \* ऑल इंडिया पी वी सी प्लोरिंग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन—नई दिल्ली
  - \* इंडियन प्लास्टिक्स फैडरेशन, कलकत्ता
  - \* गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद
  - \* ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली
  - \* ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई।
- इनमें से किसी भी पार्टी ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।
- X. पी वी सी रेजिन मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (इसके बाद इसे प्रेमा कहा जाएगा) को भी एक प्रश्नावली भेजी गई जिसमें नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। प्रेमा ने सूचना भेजने के लिए 31-1-1997 तक का समय मांगा था। यह समयवृद्धि 10-1-1997 तक दी गई थी। प्रेमा ने फिर से 31-1-97 तक समयवृद्धि की मांग के लिए अनुरोध किया और कहा कि वे विदेश के स्रोतों से पाटन संबंधी सूचना एकत्र कर रहे हैं। प्राधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 31-1-97 तक समयवृद्धि दी थी कि जांच के लिए अन्य किसी भी पार्टी ने कोई सूचना नहीं दी थी तथा प्रेमा द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना काफी महत्वपूर्ण थी। इस संबंध में प्रेमा ने 30-1-97 को उत्तर भेज दिया था।
- XI. प्राधिकारी ने मौखिक रूप से विचारों को सुनने के लिए 20 अगस्त, 1997 को सार्वजनिक सुनवाई प्रारंभ की जिसमें निम्नलिखित ने भाग लिया था :
- \* पी वी सी रेजिन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन
  - \* ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज

दी आल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चर्स ने लिखित में अपनी टिप्पणियां भेज दी थी यद्यपि उसने स्वयं सुनवाई में भाग नहीं लिया था। इन निष्कर्षों को अधिसूचित करते समय प्राप्त लिखित टिप्पणियों पर भी विचार किया गया है।

सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाली पार्टियों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित में प्रस्तुत कर दें। पार्टियों को विरोधी पार्टियों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए भी अनुरोध किया गया था तथा उसके लिए उसका खंडन करने के लिए भी कहा गया था।

XII. प्राधिकारी के पास रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के गैर-गोपनीय रूपांतर उपलब्ध थे जो किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रखे गए थे।

XIII. यह जांच 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 1996 तक की अवधि के लिए की गई थी।

#### (ख) प्रेमा के विचार

3. पी वी सी रेसिन मेनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने निम्नलिखित अनुरोध किए :

- (i) प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनंतिम शुल्कों की तुलना में अंतिम शुल्कों में कमी किए जाने के बावजूद, आयातकों ने अतिरिक्त शुल्क की वापसी का दावा नहीं किया है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रति-पाटन शुल्क का स्तर न्यायसंगत है।
- (ii) पांच भारतीय पी वी सी उत्पादकों द्वारा उठाई जाने वाली क्षति का स्तर जो कि घरेलू क्षमता का 50% से ज्यादा है, उसका मूल्य 3208 रु. प्रति मी. टन है। चूंकि डम्पिंग मार्जिन भी बढ़ गया है, इसलिए प्रति-पाटन शुल्क के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आई पी सी एल के हाल ही में लगाए गए संयंत्र की उत्पादन लागत पर भी विचार किया जाता है तो क्षति का स्तर 9300 रु. प्रति मी. टन से अधिक होगा। घरेलू उद्योग द्वारा जो कीमत दबाव, कीमतों में गिरावट, उत्पादन विक्री तथा वृद्धि के मामलों में नुकसान वहन किया जा रहा है वह ब्राजील को छोड़कर अन्य सम्बद्ध देशों से किए गए आयातों का ही प्रत्यक्ष परिणाम था। ब्राजील से आयात अनियमित रहे। क्षति पहुँचाने वाले किसी अन्य कारक ने उद्योग को उचित प्रतिफल (लाभ) कमाने से नहीं रोका है।
- (iii) ब्राजील के अतिरिक्त सभी देशों के लिए प्रति-पाटन शुल्कों का वर्तमान स्तर पूरी तरह अपर्याप्त है। ब्राजील ने बहुत थोड़ी मात्रा (75 मी. टन) निर्यात की है।

#### (iv) डम्पिंग के बारे में

- (क) संबंध देशों की मंशा का इस तथ्य से पता लगाया जा सकता है कि अक्टूबर—अप्रैल 1996 के बीच आयात बहुत अधिक हुए जो 1152 मी. टन (यू एस ए) 1463 मी. टन (कोरिया गणराज्य) के स्तर पर थे। कोरिया गणराज्य ने अक्टूबर, 1996 के महीने में यू एस डालर 600 प्रति मी. टन सी आई एफ पर निर्यात किया जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें यू एस डालर 680—710 प्रति मी. टन के बीच थीं।
- (ख) भारत को किए गए निर्यात की एफ ओ बी कीमतों तथा यू एस ए तथा कोरिया गणराज्य में आंतरिक बाजार कीमत की प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि इन देशों के निर्यातक अभी भी अपने उत्पादों की डम्पिंग कर रहे हैं। यह बात नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट हो जाती है

यू एस डालर प्र. मी. टन

अवधि	यू एस ए		कोरिया गणराज्य	
	आंतरिक बाजार कीमतें	निर्यात कीमतें	आंतरिक बाजार कीमतें	निर्यात कीमत
क्यू 2, 1995	1018	950	1058	1019
क्यू 3, 1995	949	1010	1036	670
क्यू 4, 1995	766	679	786	659
क्यू 1, 1996	702	524	744	593
क्यू 2, 95 की तुलना में	316	426	314	426
क्यू 1, 96 में गिरावट	(31%)	(45%)	(30%)	(42%)

- (ग) यद्यपि घरेलू तथा साथ ही साथ निर्यात कीमतें दोनों ही में गिरावट आई लेकिन आंतरिक बाजार कीमत (30-31%) की तुलना में निर्यात कीमत (42-45%) में अधिक तेजी से गिरावट आई।

## (iv) क्षति के बारे में

- (क) दक्षिण कोरिया और यू एस ए से हुई डम्पिंग ने घरेलू उत्पादकों को कीमतों में बहुत कमी करने को मजबूर किया जिससे उन्हें भारी क्षति हुई।
- (ख) घरेलू उत्पादकों को अपनी पहले से गिरती कीमतों पर पर्याप्त व्यापार छूट तथा ऋण फायदे देने पड़े ताकि वे डम्प आयातों की तैयार उपलब्धता से मुकाबला कर सकें। औसत वसूली मूल कीमतों से 2760 रु. प्रति मी. टन (94-95) तथा 3194 रु. प्रति मी. टन (95-96) कम हो गई। घरेलू विनिर्माता कीमतों में वृद्धि नहीं कर सके जो अन्यथा प्रमुख निविष्टियों, जैसे एथीलीन, ई डी सी तथा वी सी एम की कीमतों में तीव्र वृद्धि की वजह से बढ़ाई जानी थी।
- (ग) यू एस ए में निर्यातयोग्य अधिशेष क्षमता क्यू 2, 1995 में 197 के एम टी थी जो क्यू 1, 1996 में बढ़कर 273 के एम टी हो गई, जबकि यह कोरिया गणराज्य के मामले में संगत अवधि में दुगुनी हो गई। इस उपलब्ध अधिशेष क्षमता ने भारतीय उद्योग को कठिनाई में डाल दिया है, जिसकी क्षमता इस शताब्दी तक 1 मिलियन टन को पार कर जाने की उम्मीद है। संबंधित देशों के पास निम्नलिखित अधिशेष क्षमताएं हैं

## (आंकड़े के एम टी में)

देश	1996	1997	1998	1999
यू एस ए	1661	1657	2058	2084
कोरिया गणराज्य	135	226	294	233
मैक्सिको	238	229	211	198
ब्राजील	114	102	72	59

- (घ) भारत में पी वी सी की मांग में 13% तक वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है जो 2000 तक 8 लाख टन को पार कर लेगी। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष उपलब्ध क्षमता हो जाएगी जैसा कि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है।

आंकड़े 1000 मी. टन में	96/97	97/98	98/99	99/2000
भारतीय पी वी सी उपभोग	567	641	725	819
भारतीय पी वी सी क्षमता	813	813	893	1043
अधिशेष अप्रयुक्त क्षमता	246	172	168	224

- (ङ) देश में ही विशाल अधिशेष क्षमता को ध्यान में रखते हुए पी वी सी के लगातार आयात के परिणाम स्वरूप क्षमता उपयोग में केवल मंदी ही आएगी।
- (च) इस अवधि के दौरान बिक्री तथा क्षमता उपयोग में गिरावट आई है जबकि माल सूची बढ़ी है।
- (छ) जांच अवधि के दौरान औसत मासिक घरेलू बिक्री के प्रतिशत के रूप में अन्तिम स्टॉक औसतन 80% से अधिक रहा और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
- (ज) आई पी सी एल ने हाल ही में 150 कि.मी. वाला संयंत्र लगाया है।
- (झ) डम्प किए गए आयातों के खतरे से घरेलू उद्योग के योजनाकृत निवेश और आगे वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- (व) प्राधिकारी को शुल्क निम्नानुसार संशोधित करने चाहिए :—

रु. प्रति मी. टन

देश	मौजूदा शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
मैक्सिको	1619	3208
कोरिया गणराज्य	1253	3208
यू एस ए	504	2304
ब्राजील	2036	2036

- (vi) उपर्युक्त शुल्क तुरंत प्रभाव से पांच वर्षों के लिए लगाए जाने चाहिए क्योंकि विश्व पी वी सी उद्योग के माँग-आपूर्ति संतुलन के निकट पहुँचने के लिए यह न्यूनतम समय सीमा है।

**ग. निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार**

4. किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेजी और कोई टिप्पणी नहीं भेजी है। उपभोक्ताओं की संस्थाओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

- (i) आयातों की पहुँच कीमत देशी कीमतों से बहुत अधिक है।
- (ii) कच्चे माल की ऊँची कीमतों के कारण गत तीन वर्षों में पी वी सी प्लास्टिक उद्योग की वृद्धि में गिरावट आई है;
- (iii) भारत में प्लास्टिक का प्रति व्यक्ति उपभोग एशियाई क्षेत्र तथा विश्व में लगभग सबसे कम है;
- (iv) कच्चे माल की ऊँची कीमतों के कारण निर्यातों में मंदी रही है;
- (v) पी वी सी उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं तथा ऐसी पारम्परिक सामग्री प्रतिस्थापन करते हैं जिसके सीमित स्रोत हैं ;
- (vi) पी वी सी रेसिन पर से प्रति पाटन शुल्क हटा लेना चाहिए, मुख्यतः निम्नलिखित को ध्यान में रखकर;
  - \* परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण;
  - \* पी वी सी प्लास्टिक उद्योग की वृद्धि को बढ़ाना जिससे इसके उपभोग में भी वृद्धि होगी;
  - \* पी वी सी प्लास्टिक उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाना।
- (vii) पी वी सी रेसिन की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें विश्व में बाजार परिस्थितियों के अनुसार घटती-बढ़ती रहती हैं। पी वी सी रेसिन की कीमतें जून, 1993 में 500 यू एस डालर प्रति मी. टन थीं जो बढ़कर वर्तमान में 700 यू एस डालर प्रति मी. टन हो गई हैं (संगत अवधि में विनिमय दर भी 26 रु. प्रति यू एस डालर से बढ़कर 36 रु. प्रति यू एस डालर हो गई है)। हालाँकि पी वी सी रेसिन की कीमतें अधिक हुई हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है लेकिन संगत अवधि में इसकी उत्पादन सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (viii) अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के संदर्भ में संसाधकों को विश्व बाजार कीमतों का लाभ अवश्य दिया जाना चाहिए।
- (ix) घरेलू उत्पादक जो विश्व क्षमता संयंत्र रखने का दावा करते हैं, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत के अनुसार अपनी कीमतें बढ़ाना जारी रखा। एक उत्पादक ने विश्व बाजार कीमत की बराबरी करने के लिए अपनी कीमतों को एक महीने में चार बार बढ़ाया है।

**(घ) प्राधिकारी द्वारा जाँच**

5. प्रेमा, उपभोक्ता संगठनों तथा अन्य संबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों की जाँच की गई और उन पर विचार किया गया, “जहाँ कहीं उपयुक्त समझा गया वहाँ इसके बाद कार्रवाई की गई है”।
6. प्रेमा का यह दावा कि जिन आयातकों ने अनन्तिम तौर पर लगाए गए प्रति पाटन शुल्क की अधिक राशि का भुगतान किया लेकिन अन्तिम रूप से कम प्रति पाटन शुल्क लागू होने के बाद वापसी का दावा नहीं किया, मौजूदा समीक्षा के निर्णय के संदर्भ में असंगत है।
7. प्रेमा के इस अनुरोध का कोई कानूनी आधार नहीं है कि प्रस्तावित संशोधित शुल्क पाँच वर्ष के लिए इस आधार पर लगाया जाय कि यह समयावधि विश्वव्यापी पी वी सी उद्योग को माँग-आपूर्ति संतुलन को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अवधि है, जबकि प्रति पाटन नियम, प्रतिपाटन शुल्क पाँच साल के लिए लगाए जाने की अनुमति देते हैं। फिर भी इस नियम में इस समयावधि की समाप्ति से पूर्व पुनरीक्षा का प्रावधान है।

**(ङ) विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुएं**

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुओं के बारे में पूर्व में अधिसूचित अन्तिम जाँच परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

**(च) घरेलू उद्योग**

पहले की गई जाँच में प्राधिकारी ने प्रेमा द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग के रूप में निम्नलिखित एककों पर विचार किया था :—

केमप्लास्ट सनमार लिमि.

\* रिलायान्स इंडस्ट्रीज लिमि.

\* डी सी एम श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमि.

\* डी सी डब्ल्यू लिमि.

यह पाया गया कि प्रेमा ने प्राधिकारी के अनुरोध पर आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के परिणाम सहित क्षति के संदर्भ में सूचना दी है।

- \* डी सी एम श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमि.
- \* डी सी एम लिमि.
- \* केमप्लास सनमार लिमि.
- \* फिनोलेक्स पाइप्स लिमि.
- \* नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमि.

प्रेमा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह पाया गया है कि प्रेमा ने जिन एककों के संबंध में जानकारी दी है उन एककों का सामूहिक उत्पादन भारत में पी वी सी रेसिन का अधिकांश उत्पादन नहीं है। इसलिए प्रेमा से अन्य भारतीय उत्पादकों के बारे में भी सूचना देने का अनुरोध किया गया था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रेमा ने जो सूचना प्रस्तुत की है वह भारत में पी वी सी रेसिन के अधिकांश उत्पादन से संबंधित है। प्रेमा ने रिलायान्स इंडस्ट्रीज लिमि; के संबंध में सूचना दी। इस प्रकार प्रेमा ने निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों के संबंध में सूचना दी है।

- \* डी सी एम श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमि.
- \* डी सी डब्ल्यू लिमि.
- \* केमप्लास सनमार लिमि.
- \* फिनोलेक्स पाइप्स लिमि.
- \* नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमि.
- \* रिलायान्स इंडस्ट्रीज लिमि.

उपर्युक्त एककों के सामूहिक उत्पादन पी वी सी रेजिन के कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। ये कम्पनियाँ इसलिए सामूहिक रूप से नियमों की परिधि में घरेलू उद्योग की परिभाषा में आती हैं।

#### (ज) पाटन

##### सामान्य मूल्य

- II. प्राधिकारी ने धारा 9क (1) ग के अनुसार सामान्य कीमत में निर्धारण के उद्देश्य से सभी ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक संबंधी प्रश्नावलियाँ भेजी। लेकिन किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं भेजा और कोई सूचना नहीं भेजी है। इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि संबंधित देशों के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया जैसाकि नियमों में परिकल्पित है।

प्रेमा ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में सूचना भेजी है जिस पर नीचे विचार-विमर्श किया गया है।

##### प्रेमा द्वारा पाटन के बारे में किए गए दावे

यू एस ए और कोरिया के मामले में सामान्य मूल्य को निर्धारण आर्थर डी लिट्ल, यू के द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर किया जा सकता है। मेक्सिको के मामले में घरेलू मूल्य का दावा अमरीका के समतुल्य आयात मूल्य, 7% टैरिफ दर, मेक्सिको में आयातित पी वी सी रेजिन पर देय 90 अमरीकी डालर प्रति मी. टन भाड़ा और 40 प्रति मी. टन अमरीकी डालर की परिवहन लागत के अंतर के आधार पर किया गया है। प्रेमा द्वारा संबंधित देशों के लिए दावा किया गया सामान्य मूल्य निम्नानुसार है;

अवधि	यू एस ए	कोरिया गणराज्य	मैक्सिको	ब्राजील
क्यू 2, 95	1018	1058	1359	970
क्यू 3, 95	949	1036	1274	1000
क्यू 4, 95	766	786	1049	970
क्यू 1, 96	702	744	970	842
क्यू 2, क्यू 1	316	314	389	128
तक गिरावट	31%	30%	29%	13%

मैक्सिको के मामले में उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार और यू एस ए और कोरिया गणराज्य के मामले में नीचे के ब्यौरे के अनुसार ये मूल्य परिवहन और पैकिंग लागत के अंतर के लिए समायोजन किए जाने के बाद के मूल्य हैं।

**यू एस ए और कोरिया गणराज्य के मामले में प्रेमा द्वारा दावाकृत घरेलू बाजार मूल्य में समायोजन**

यू एस ए रेलकार द्वारा बड़ी मात्रा में डिलीवरी के विपरीत 25 किग्रा. के पैक में डिलीवरी के लिए 44 अमरीकी डालर प्रति मी. टन का पैकिंग प्रीमियम, परिवहन लागत में अंतर (घरेलू मामले में 24) अमरीकी डालर प्रति मी. टन और निर्यातों के मामले में 10 अमरीकी डालर प्रति मी. टन है।

कोरिया गणराज्य : दोनों गन्तव्य स्थल समान दूरी पर होने के कारण भाड़े में कोई अंतर नहीं है।

सम्बद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा कोई सूचना नहीं भेजे जाने और इस मामले के विरोध में या समर्थन में कोई अन्य सूचना उपलब्ध न होने के कारण प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रेमा के दावे के आधार पर किया है।

**निर्यात कीमत**

14. प्रेमा ने निर्यात मूल्य का दावा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एण्ड एस) द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर किया था। हालांकि प्रेमा ने यह दावा किया था कि सीमाशुल्क की दैनिक सूचियों के अनुसार आयात की मात्रा डी जी सी आई एण्ड एस द्वारा दर्शाई गई मात्रा की तुलना में अधिक है, लेकिन इसने अपने अनुरोध में इस बात पर कोई विवाद नहीं किया था कि डी जी सी आई एण्ड एस द्वारा संकलित आंकड़ों में दर्शाई गई निर्यात कीमत संबद्ध देशों से आयात की गई पी वी सी रेजिन की सही निर्यात कीमत है। तथापि, यह तर्क, प्राधिकारी द्वारा उजागर किए गए तथ्य के बाद किया गया है कि डी जी सी आई एण्ड एस द्वारा दर्शाई निर्यात कीमत को सीमाशुल्क निकासी की दैनिक रिपोर्टों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रेमा ने यह तर्क प्राधिकारी द्वारा आवश्यक तथ्य उजागर किए जाने के बाद किया है। इसके अलावा, प्रेमा ने दैनिक सीमाशुल्क निकासियों से निर्यात कीमत की जो गणना की है, वह मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास पोरबन्दर तथा काण्डला पत्तनों से संकलित की गई जानकारी पर आधारित है, जबकि डी जी सी आई एण्ड एस द्वारा संकलित की गई सूचना में भारत के सभी पत्तनों को कवर किया गया है। अतः यह सूचना अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। प्रेमा द्वारा किए गए दावे को स्वीकार नहीं करने का कारण केवल यही नहीं है कि यह दावा प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के उजागर किए जाने के बाद प्रस्तुत किया गया है, अपितु इसका कारण यह भी है कि संकलित जानकारी सभी भारतीय पत्तनों से संबंधित नहीं है। अतः प्राधिकारी इसे उचित मानता है कि निर्यात मूल्य का निर्धारण डी जी सी आई एण्ड एस द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाए।
15. प्रेमा ने समुद्री माल भाड़े तथा बीमा का दावा यू एस ए के मामले में 100 यू एस डालर प्रति मी. टन, कोरिया गणराज्य के मामले में 70 यू एस डालर प्रति मी टन, मैक्सिको के मामले में 120 यू एस डालर प्र. मी. टन एवं ब्राजील के मामले में 145 यू एस डालर प्र. मी. टन का दावा किया है। प्राधिकारी ने समुद्री माल भाड़े और बीमा के समायोजन की अनुमति प्रेमा द्वारा किए गए दावे के अनुसार दी है।

इस प्रकार निर्धारित की गई निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य को कारखाना द्वार पर की गई बिक्री कीमत माना गया है। चूंकि कथित देशों से किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी के सूचना देने के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने अलग-अलग निर्यातकों के लिए पाटन सीमा का निर्धारण नहीं किया है। प्राधिकारी ने प्रेमा द्वारा प्रस्तुत सूचना को हिसाब में लिया क्योंकि अन्य किसी भी पार्टी ने कथित देशों में से प्रत्येक के लिए सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों के बीच उचित तुलना के उद्देश्य से कोई भी विषयात्मक सूचना प्रस्तुत नहीं की और न ही सामान्य मूल्य के साथ भारत औसत निर्यात कीमत की तुलना की। यह तुलना निम्नांकित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन सीमा दर्शाती है :

**यू एस डालर प्रति मी. टन**

देश	पाटन सीमा
ब्राजील	14
कोरिया गणराज्य	318
मैक्सिको	313
यू एस ए	64

**ज. क्षति और कारणात्मक संबंध**

अप्रैल, 1996 के बाद पी वी सी रेजिन का आयात वर्तमान जांच में पाटन तथा/या क्षति का निर्णय करने के लिए अप्रासंगिक है। प्रेमा का यह कथन भी साबित नहीं किया जा सकता कि कोरिया गणराज्य तथा/या यू एस ए से पाटन किए जाने से घरेलू उत्पादकों द्वारा कीमतों में भारी गिरावट की गई। ऐसा पाया गया है कि कोरिया गणराज्य और यू एस ए से आयात क्रमशः 42125 रु. और 41367 रु. प्रति मी टन की औसत कीमत पर आए, जबकि प्रेमा के दावे के अनुसार घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत रु. प्र. मी. टन थी। चूंकि कथित देशों से आयातों का भारतीय बाजार में प्रवेश घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई उचित बिक्री कीमत से काफी ज्यादा कीमत पर हुआ, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कथित देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इस प्रकार, उचित बिक्री कीमत तथा घरेलू उद्योग द्वारा निवल प्राप्ति के बीच किसी अन्तर के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

प्रेमा का यह दावा सिद्ध नहीं होता है कि डम्प किए गए आयातों को देखते हुए घरेलू उत्पादकों को अपनी पहले से ही गिरती हुई कीमतों पर काफी व्यापार छूट तथा/अथवा ऋण लाभ देना पड़ा। डम्प किए गए आयात प्रेमा द्वारा दावा किए गए उचित बिक्री मूल्य से काफी अधिक कीमतों पर उपलब्ध थे। इसलिए इन्हें व्यापार छूट देने अथवा कम निवल प्राप्तियों के लिए एक कारण नहीं माना जा सकता है।

प्रेमा का यह दावा भी सिद्ध नहीं हो सकता है कि पाटित आयातों को देखते हुए कीमत में वृद्धि करने से घरेलू उत्पादकों को रोका गया, जो कि मुख्य निवेशों की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण की जानी थी, क्योंकि घरेलू उद्योग को जो उचित बिक्री कीमत मिलनी चाहिए थी उससे काफी ज्यादा कीमतों पर आयातित उत्पाद उपलब्ध थे। इस प्रकार जहाँ तक संबद्ध देशों से आयातों का संबंध है वहाँ इन देशों से आयातित वस्तुओं की पहुँच कीमत तक कीमत वृद्धि करने के लिए घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त लोचशीलता की गुंजाईश थी। इस प्रकार पाटित आयातों की उपलब्धता को मूल्य वृद्धि करने में घरेलू उत्पादकों की असमर्थता का भी कारण नहीं माना जा सकता।

प्रेमा के इस दावे से भी कि कथित देशों ने अत्यधिक निर्यात योग्य क्षमता पैदा कर दी है, से भी पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को किसी क्षति का होना प्रमाणित नहीं होता। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग को डम्पिंग से कोई क्षति हुई है क्योंकि इन देशों से निर्यातकों ने वस्तुओं का निर्यात जिस पहुँच कीमतों पर किया वह घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत से काफी ज्यादा थी। भविष्य में कथित देशों में उपलब्ध हो सकने वाली बेशी क्षमता भी अप्रासंगिक है।

जाँच अवधि के दौरान या भविष्य में भारत में बिना उपयोग की हुई बेशी क्षमता से यह प्रमाणित नहीं होता है कि समीक्षा की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षति हुई।

प्रेमा ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि पाँच घरेलू उत्पादकों द्वारा उचित बिक्री कीमत की तुलना में 3208 रु. प्रति मी. टन कम प्राप्ति पाटित आयातों के कारण हुई है। यह तर्क कि आई पी सी एल के हाल ही में चालू किए गए संयंत्र की उत्पादन लागत पर विचार करने के बाद क्षति का स्तर 9300 रु. प्रति मी टन से ज्यादा हो जाएगा, प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है।

#### ४. पहुँच कीमत

46. पहुँच कीमत की गणना सीमाशुल्क की चालू दर और एक प्रतिशत उतराई तथा दो प्रतिशत रखरखाव शुल्क को जोड़कर डी जी आई एण्ड एस द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत औसत निर्यात कीमत पर विचार करके की गई है। इन देशों से आयातों पर लागू प्रतिपाटन शुल्क को पहुँच कीमत में शामिल नहीं किया गया है। प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग पहुँच कीमत की गणना की गई है।

#### अन्य मुद्दे

ब्राजील से किए गए आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क हटाने का औचित्य इस तथ्य के बाद भी नहीं है कि वहाँ से बहुत ही कम मात्रा का आयात किया गया, भले ही मात्रा अत्यन्त कम हो। प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने के बाद कथित वस्तुओं के आयात को ऐसी वस्तुओं पर लागू प्रतिपाटन शुल्क के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इनमें से किसी भी देश से आयात की कम मात्रा प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप हो सकती है। इस प्रकार, किसी उत्पाद पर लागू किए गए प्रतिपाटन शुल्क को सिर्फ इस आधार पर हटाना सही नहीं होगा कि आयात बहुत ही कम है।

#### अंतिम जाँच-परिणाम

31. उपर्युक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :

- \* संबद्ध देशों से उद्गम वाले या वहाँ से निर्यात किए गए पी वी सी रेजिन का भारत में निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया, जिससे पाटन हुआ।
- \* संबद्ध देशों से पी वी सी रेजिन के आयात से घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
- \* संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पी वी सी रेजिन के निर्यात की वजह से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

28. यह उपयुक्त समझा गया है कि यू एस ए, ब्राजील, मैक्सिको तथा कोरिया गणराज्य मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पी वी सी रेजिन के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाए। तथापि, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर प्राधिकारी यह शुल्क लगाए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व इन निष्कर्षों की समीक्षा कर सकता है।

29. उपर्युक्त बातों के अध्यक्षीन दिनांक 30 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं. 14/4/92-टी पी डी द्वारा अधिसूचित अन्तिम जाँच-परिणामों की पुष्टि की जाती है।

30. इस आदेश के विरुद्ध अपील उक्त अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वयं (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में की जा सकेगी।

दीपक चटर्जी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1997

Subject: Review of Anti-dumping duties concerning Imports of PVC Resin - final findings

ADD/IW/53/96.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. **PROCEDURE**

1. The Procedure described below has been followed:
  - i. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) issued a public notice vide Notification no. ADD/IW/53/96 dated the 30th Sept., 1996, initiating review of definitive Anti-dumping duties recommended on imports of Poly Vinyl Chloride Resin (also referred to as PVC Resin hereinafter) originating in or exported from Brazil, Republic of Korea (also referred to as Korea or Korea RP hereinafter), Mexico and the United States of America (also referred to as USA hereinafter) vide notification no. 14/4/92-TPD dated 30th July, 1993 and definitive Anti Dumping Duties imposed by the Central Government vide notification no. 4/94 dated 18th Jan., 1994.
  - ii The investigations concluded by the Designated Authority vide Notification no. 14/4/92-TPD dated 30th July, 1993 have been referred to as "the previous investigations";
  - iii The Authority issued a public notice dated 30th Sept., 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating review of anti-dumping duties concerning imports of PVC Resin, classified under custom heading 3904 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from

Brazil Korea RP, Mexico and USA (also referred to as the subject countries hereinafter):

- iv. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters and industry associations (whose details were made available by PVC Resin Manufacturers' Association in the previous investigations) and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the rule 6(2);
- v. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known associations of consumers of PVC Resin in India (whose details were made available by PREMA in the previous investigations) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;
- vi. Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of import of PVC Resin made in India during the past three years, including the period of review. No information was however, received from CBEC;
- vii. The Authority sent questionnaire, to elicit relevant information, to the following exporters, in accordance with the rule 6(4);
  - ◆ Vista Chemical Company, USA;
  - ◆ Shintech Inc., USA;
  - ◆ Borden Chemicals & Plastics, USA;
  - ◆ Formsa Plastics Corp., USA;
  - ◆ Lucky Goldstar International, Korea RP;
  - ◆ Hangyang Chemical Corp., Korea RP;
  - ◆ Grupo Primex, S. A. DE C.V., Mexico;
  - ◆ U B International, Singapore;
  - ◆ Vinmar Inc., USA;
  - ◆ Companhia Petroquímica, Brazil;
  - ◆ Kunstoplast of America Inc., USA

None of the exporters, however, filed response to the questionnaire.

- viii. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the review in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassies, alongwith a list of known exporters/producers;
- ix. A questionnaire was sent to the following associations of consumers of PVC Resin in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4):
- ◆ Organisation of Plastics Processors of India, Mumbai;
  - ◆ All India Cloth Association, Mumbai;
  - ◆ All India PVC Flooring Manufacturers Association, New Delhi;
  - ◆ Indian Plastics Federation, Calcutta;
  - ◆ Gujarat State Plastic Manufacturers Association, Ahmedabad;
  - ◆ All India Federation of Plastic Industries, New Delhi;
  - ◆ All India Plastics Manufacturers Association, Mumbai.

None of the parties, however, filed response to the questionnaire.

- x. A questionnaire was sent to PVC Resin Manufacturers' Association (herein referred to as PREMA also) calling for necessary information in accordance with rule 6(4). PREMA requested for time upto 31.1.1997 to file information. The extension was allowed upto 10.1.1997. PREMA, however, again requested time upto 31.1.1997, pleading that it was collecting information on dumping from overseas sources. The Authority allowed time upto 31.1.1997 in view of the fact that none of the other parties to the investigations furnished any information and the information to be furnished by PREMA was of significant importance. Response was filed by PREMA on 30.1.1997.
- xi. The Authority held a public hearing on 20th Aug., 1997 to hear the views orally, which was attended by the following:
- PVC Resin Manufacturers Association;

**All India Federation of Plastic Industries.**

The All India Plastic Manufacturers Association sent their written comments, though the association did not attend the hearing. The written comments received have been considered while notifying these findings.

The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to offer their rebuttals;

- xii. The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained and kept open for inspection by an interested party.
- xiii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 1995 to 31st March, 1996.
- xiv. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings.

**B. VIEWS OF PREMA**

- 2. PVC Resin Manufacturers' Association made the following submissions:
  - i) Despite reduction in definitive duties as compared to provisional duties recommended by the Authority, the importers did not claim a refund of excess duty. It may be concluded that the level of anti-dumping duty stands vindicated.
  - ii) The level of injury suffered by the five Indian PVC producers, accounting for over 50% of domestic capacity is to the tune of Rs. 3208 pmt. Since dumping margin has also increased there is a need to increase the level of anti-dumping

IPCL's recently commissioned plant are also considered. Price depression, price suppression, loss of production, sale and growth suffered by the domestic Industry were a direct consequence of Imports from the subject countries other than Brazil. Imports from Brazil have been erratic. No other factor causing Injury can be termed to have denied a fair return to the industry.

iii) The present level of anti-dumping duties for all countries except Brazil is absolutely inadequate. Brazil has exported very small quantities (75 MT).

iv) On Dumping:

a) The mindset of the subject countries can be gauged by the fact that imports between April-October 1996 were very high at 1152 MT (USA), 1463 MT (Korea RP). Korea RP exported at US \$ 600 pmt CIF in the month of October, 1996 when the international prices were moving in the range of US \$ 680-710 pmt.

b) The trend of FOB export prices to India and home market price in USA and Korea RP establish that the exporters from these countries are still dumping their products. This is evident from the table below:

US \$ pmt

Period	USA		Korea RP	
	Home Market Prices	Export price	Home Market Prices	Export price
Q 2, 1995	1018	950	1058	1019
Q 3, 1995	949	1010	1036	670
Q 4, 1995	766	679	786	659
Q 1, 1996	702	524	744	593
Decline in Q 1, 96 as compared to Q 2, 95	316 (31%)	426 (45%)	314 (30%)	426 (42%)

- c) Though both domestic as well as export prices have declined, the decline in the export price (42-45%) is much sharper than decline in the home market price (30-31%).
- d) In response to the disclosure of essential facts made by the Authority, PREMA contended that the export price should be determined on the basis of Daily Customs Clearance reports published by various Customs House in ports, in view of the following.
  - i. In the data compiled by DGCI&S, in case the information supplied by a port is delayed by over six months, then the DGCI&S does not reflect the information as per clearance dates but reflects the information on the basis of their own compilation, thus distorting the imports quantity and prices.
  - ii. Customs authorities have been clearing Emulsion/Paste grade resin (ITC code 39042101) under the tariff code of Suspension grade (ITC codes 39041000/ 39042102/ 39042109).

PREMA requested for an oral hearing to elaborate these submissions.

▼) On injury:

- a) The dumping from South Korea and USA has led to drastic reduction in prices by the domestic producers causing grave injury.
- b) Domestic producers had to offer substantial trade discounts and credit benefits on their already declining prices in order to compete with the ready availability of dumped imports. The average realisations fell short of basic prices by Rs. 2760 pmt (94-95) and Rs. 3194 pmt (95-96) The domestic manufactures were prevented from effecting price increases which otherwise were due in view of steep hike in prices of major in-puts, such as Ethylene, EDC and VCM
- c) The exportable surplus capacity in USA rose to 273 kMT in Q 1, 1996 from 197 kMT in Q 2, 1995, whereas the same doubled in case of Korea RP in the corresponding period. The surplus capacity available pose a threat to Indian

industry, capacity of which is expected to cross 1 million tonnes by the turn of the century. The subject countries have the following surplus capacities:

(figures in k MT)

Country	1996	1997	1998	1999
USA	1661	1657	2058	2084
Korea RP	135	226	294	233
Mexico	238	229	211	198
Brazil	114	102	72	59

- d) The demand for PVC in India is projected to grow at a healthy 13% to cross 8 lakh tonnes by 2000 resulting in surplus available capacity as may be seen from the following table:

(Figs in '000 MT)	96/97	97/98	98/99	99/2000
Indian PVC Consumption	567	641	725	819
Indian PVC Capacity	813	813	893	1043
Surplus Unutilised Capacity	246	172	168	224

- e) In view of huge surplus capacity within the country, continuous imports of PVC will only result in depressing the capacity utilisation.
- f) Sales and capacity utilisation have declined during the period whereas Inventory has increased.
- g) Closing stocks as a percentage of average monthly domestic sales have averaged at more than 80% during investigation period and the same are continually climbing.
- h) IPCL has recently commissioned a 150 kmt plant.
- i) Threats from dumped imports may adversely affect planned investments and further growth of the domestic industry.

- v) The Authority should revise duties as follows:

Rs. per MT

Country	Existing duties	Proposed duties
Mexico	1619	3208
Korea RP	1253	3208
USA	504	2304
Brazil	2036	2036

- vi) The above duties should be levied for five years with immediate effect as the same is the minimum time frame for the global PVC industry to reach near demand-supply balance.

C. **VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

- 3 None of the exporters has responded to the Authority and offered any comments. The associations of the consumers have expressed their views, and the same are briefly mentioned below:

- i) The landed price of imports is significantly higher than indigenous prices;
- ii) The PVC Plastic industry has experienced retarded growth in the last three years due to high prices of raw materials;
- iii) The per capita consumption of Plastic in India is amongst the lowest in the Asian Region and the world;
- iv) There has been a slow down in exports due to high prices of raw materials;
- v) PVC products are eco-friendly and replace conventional materials which are limited resources;
- vi) The anti-dumping duties on PVC Resin should be withdrawn, especially in view of the following

- ♦ the changed international environment;
  - ♦ accelerating the growth of the PVC Plastics industry which would increase its consumption also;
  - ♦ Increasing exports of PVC Plastic products.
- vii) International price of PVC Resin has been fluctuating according to market conditions in the world. Price of PVC Resin has gone up from US \$ 500 pmt In Jan., 1993 to US \$ 700 pmt at present (with the exchange rate also increasing from Rs. 26 per US \$ to Rs. 36 per US \$ in the corresponding period). Whereas the prices of PVC Resin have gone up, as stated above, there has been no change in the prices of feedstock in the corresponding period.
- viii) The processors must be given advantage of the world market prices in the context of liberalisation of economy
- ix) Domestic producers who claim to have world capacity plants keep increasing their prices according to the international market price. One of the producers increased its prices four times in a month to align with the world market price.

#### D EXAMINATION BY AUTHORITY

4. The submissions made by PREMA, consumer associations and other interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, have been dealt hereinafter.
5. The claim of PREMA that the importers who had paid excess anti-dumping duty provisionally levied and did not claim refund after imposition of lower definitive anti-dumping duty is irrelevant to decide the present review.
6. The request of PREMA that the revised duties requested should be levied for five years on the grounds that the this time period is the minimum time frame for the global PVC industry to reach near demand-supply balance is not supported by law, as the anti-dumping rules permit levy of anti-dumping duty

for a period of five years, albeit with a provision of review before the expiry of the period.

E. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLES**

7. The final findings notified earlier with regard to the product under consideration and like articles remains unchanged.

F. **DOMESTIC INDUSTRY**

8. In the investigations conducted earlier, the Authority had considered the following units as forming part of the domestic industry, based on the information furnished by PREMA.

- ◆ Chemplast Sanmar Ltd.,
- ◆ Reliance Industries Ltd.,
- ◆ DCM Shriram Consolidated Ltd.,
- ◆ DCW Ltd.

It was found that PREMA furnished information, in response to the Authority's request, with regard to injury, including the extent of injury suffered by the domestic industry, on the basis of the data in respect of the following producers:

- ◆ DCM Shriram Consolidated Ltd.,
- ◆ DCW Ltd.,
- ◆ Chemplast Sanmar Ltd.,
- ◆ Finolex Pipes Ltd.,
- ◆ National Organic Chemical Industries Ltd.

It was found from the information filed by PREMA that collective production of units, information in respect of which was filed by PREMA, did not account for majority production of PVC Resin in India. PREMA was, therefore, requested to furnish information in respect of other Indian producers

also so as to ensure that the information furnished by PREMA accounted for majority production of PVC Resin in India. PREMA furnished information in respect of Reliance Industries Ltd. The information filed by PREMA is thus in respect of following Indian producers.

- ♦ DCM Shriram Consolidated Ltd.,
- ♦ DCW Ltd.,
- ♦ Chemplast Sanmar Ltd.,
- ♦ Finolex Pipes Ltd.,
- ♦ National Organic Chemical Industries Ltd.
- ♦ Reliance Industries Ltd.

Collective production of the above units accounted for major proportion of the total Indian production of PVC Resin. These companies, therefore, collectively constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

G. **DUMPING**

9. The Authority sent exporters questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)c. However, none of the exporters responded to the Authority and have not furnished any information. The Authority, therefore, holds that none of the exporters from the subject countries have co-operated with the Authority as envisaged under the Rules.
10. PREMA has furnished Information with regard to normal values and export prices and the same is discussed hereinbelow:

**Dumping claimed by PREMA:**

11. Normal value in case of USA and Korea may be determined on the basis of information furnished by Arthur D'Little, U.K. In case of Mexico, the domestic prices have been claimed on basis of import parity price from the US, tariff rate of 7 percent, freight of US \$ 90 pmt payable on PVC Resin imported into

Mexico and transportation cost differential of US \$ 40 pmt. The normal values claimed by PREMA for the subject countries are as under:

Period	USA	Korea RP	Mexico	Brazil
Q 2, '95	1018	1058	1359	970
Q 3, '95	949	1036	1274	1000
Q 4, '95	766	786	1049	970
Q 1, '96	702	744	970	842
Fall from Q2	316	314	389	128
to Q1	31 %	30 %	29 %	13 %

12. These prices are after adjusting the same for differences in transportation and packing costs, as detailed above in case of Mexico, and as detailed hereinbelow for USA and Korea RP.

13. Adjustments in home market prices in case of USA and Korea RP claimed by PREMA

- a. USA : Difference in transportation costs (US \$ 24 pmt in case of domestic and US \$ 10 pmt in case of exports), Packing premium of US \$ 44 pmt for delivery in 25 kgs. as opposed to bulk delivery by rail car.
- b. Korea RP: There is no freight differential as both the destinations are located at similar distances.

In view of the fact that none of the exporters from the subject countries has furnished any information and in the absence of any other information, either supporting or contradictory, the Authority has determined normal values in the subject countries on the basis of claims made by PREMA.

14. PREMA claimed export prices on the basis of data compiled by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). Though PREMA claimed that import volume as per customs daily listings are higher than the volumes as per the DGCI&S, it had not disputed in its submissions that export

price as per the statistics compiled by DGCI&S represents correct export price of PVC Resin imported from the subject countries. PREMA, however, contended in response to the Authority's disclosure of essential facts that the export price as per DGCI&S cannot have precedence over Daily Customs Clearance reports. The Authority notes that the argument has been raised by PREMA after disclosure of essential facts. Moreover, the export prices worked out by PREMA from the Customs Daily Clearances are based on information compiled from the data of Mumbai, Calcutta, Madras, Porbunder, Okha and Kandla ports, whereas the information compiled by DGCI&S covers all ports in India, and therefore, more authentic and reliable. The claim made by PREMA is not admissible not only due to the fact that the same has been made after disclosure, but also due to the fact that the information compiled is not for all ports in India. The Authority, therefore, considers it appropriate to determine export prices on the basis of statistics compiled by DGCI&S.

15. PREMA has claimed ocean freight and insurance @ US \$ 100 pmt in case of USA, US \$ 70 pmt in case of Korea RP, US \$ 120 pmt in case of Mexico and US \$ 145 pmt in case of Brazil. The Authority has allowed adjustment for ocean freight and insurance as claimed by PREMA.
16. The export prices and normal values so determined have been considered as ex-works prices.
17. Since none of the exporters from the subject countries has responded to the Authority's request for information, the Authority has not determined dumping margins for individual exporters. The Authority took into account the information furnished by PREMA, as no other party furnished any factual information, for the purpose of fair comparison between the normal values and the export prices and compared normal values with weighted average export prices, for each of the subject countries. The comparison shows the following dumping margins:

Country	Dumping margin (US \$ per MT)
Brazil	14
Korea RP	318
Mexico	313
USA	64

H. **INJURY AND CAUSAL LINK**

18. Imports of PVC Resin after April 1996 are irrelevant to decide dumping and/or injury in the present investigations. The contention of PREMA that dumping from Korea RP and/or USA led to drastic reduction in prices by the domestic producers is also unsubstantiated. It is found that imports from Korea RP and USA entered at an average price of Rs. 42125 and 41367 pmt, whereas the fair selling price of the domestic industry, as claimed by PREMA, was Rs. \*\*\*\*\* pmt. Since imports from the subject countries entered in the Indian market at prices significantly higher than the fair selling price claimed by the domestic industry, it cannot be said that the imports from the subject countries are causing injury to the domestic industry. Any difference between the fair selling price and the net realisations by the domestic industry, therefore, cannot be attributed to the dumped imports.
19. The contention of PREMA that the domestic producers had to offer substantial trade discounts and/or credit benefits on their already declining prices in view of the dumped imports is not established. The dumped imports were available at prices significantly higher than the fair selling price claimed by PREMA and, therefore, the same cannot be held as a reason for offering trade discounts or for lower net realisations.
20. The contention of PREMA that the domestic producers were prevented from effecting price increases, which were due in view of steep hike in the prices of major in-puts in view of dumped imports is also not established, as the imported products were available at prices significantly higher than the fair

selling price which the domestic industry should have received, thus leaving sufficient cushion to the domestic industry to effect any price increase upto the landed cost of the imported goods from the subject countries in so far as the imports from these countries are concerned. The reasons for inability of the domestic producers to effect price increases also cannot be, therefore, attributed to the availability of the dumped imports.

21. The contention of PREMA that the subject countries have created excess exportable capacity also does not establish any injury to the domestic industry from the dumped imports. The dumping cannot be held to have caused any injury to the domestic producers, as the goods were exported by the exporters from these countries at landed prices significantly higher than the fair selling price of the domestic industry. The surplus capacities which might be available in the subject countries in future is also irrelevant.
22. The surplus unutilised capacity in India during investigation period or in the future does not establish injury to the domestic industry.
23. PREMA has not established that the lower price realisations than the fair selling price to the extent of Rs. 3208 pmt by the domestic industry is due to dumped imports.
24. The argument that the level of injury would exceed Rs. 9300 pmt, in case production cost of IPCL's recently commissioned plant are considered, is unsubstantiated and, therefore, may be rejected.

**LANDED VALUE:**

25. The landed values have been calculated considering the weighted average export price as per the statistics compiled by DGCI&S, after adding the prevailing level of customs duties and one percent landing and two percent handling charges. Separate landed values have been calculated for each country. The anti-dumping duties in force on imports from these countries have not been included in the landed values.

**J. OTHER ISSUES**

26. The fact that Brazil has exported very small quantities does not warrant removal of anti-dumping duty on imports from Brazil, even if the volumes are de-minimus. Imports of the subject goods after imposition of anti-dumping duty have to be viewed in the context of the anti-dumping duty in force on such goods. The low volume of imports from any of these countries could be a result of the very imposition of anti-dumping duty. It would, therefore, not be appropriate to remove anti-dumping duty in force on any product merely on the ground that the imports are de-minimus.

**K. FINAL FINDINGS**

27. The Authority concludes, after considering the foregoing, that:
- PVC Resin originating in or exported from the subject countries has been exported to India below its normal value;
  - the domestic industry has not suffered any material injury from imports of PVC Resin from the subject countries;
  - no injury has not been caused to the domestic industry by the exports of PVC Resin originating in or exported from the subject countries.
28. It is considered appropriate to discontinue the anti-dumping duties in force on imports of PVC Resin on exports originating in or exported from USA, Brazil, Mexico and Korea RP. The Authority may, however, on sufficient cause being shown, review these findings before the expiry of five years from the date of first
29. Subject to above, the final findings notified vide notification no. 14/4/92-TPD dated 30th July, 1994 is confirmed.
30. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

DEEPAK CHATTERJEE, Designated Authority